IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double- Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, July 2026
Impact Factor: 8.2

लघु उद्योगांच्या विकास बँकेच्या स्थापनेत संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याची भूमिका

दीपक नारायण राऊत[1], डॉ. विभा गर्ग[2]
[1]शोधार्थी, [2]सह-प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग
मोनाड विश्वविद्यालय, हापूड

सारांश: *भारत जैसे विकासशील देश में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संतुलन, उद्यमिता विकास तथा आय के अपेक्षाकृत समान वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उद्योगों के विकास में पर्याप्त एवं समयबद्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एक प्रमुख आवश्यकता है। लघु उद्योगों की पूंजीगत सीमाओं, संपार्श्विक सुरक्षा की कमी, तकनीकी पिछड़ेपन और औपचारिक ऋण संस्थानों तक सीमित पहुँच के कारण संस्थागत वित्त पोषण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस संदर्भ में लघु उद्योगों के विकास बैंक की स्थापना को एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों को ऋण, पुनर्वित्त, तकनीकी सहायता, उद्यमिता प्रशिक्षण तथा वित्तीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। प्रस्तुत समीक्षा पत्र में लघु उद्योगों के विकास में संस्थागत वित्त की अवधारणा, आवश्यकता, प्रमुख स्रोतों, विकास बैंक की भूमिका, ऋण वितरण की समस्याओं तथा वित्तीय समावेशन के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विकास बैंक और अन्य संस्थागत वित्तीय एजेंसियाँ लघु उद्योगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।*

मुख्य संकेतक: लघु उद्योग, संस्थागत वित्त, विकास बैंक, वित्त पोषण, उद्यमिता, सूक्ष्म उद्योग, औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन।

I. परिचय

लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादन एवं रोजगार संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन उद्योगों में अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश के साथ स्थानीय संसाधनों, श्रम और उद्यमशीलता का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण में सहायक होता है। इसके बावजूद इन इकाइयों को प्रारंभिक स्थापना, कार्यशील पूंजी, मशीनरी के आधुनिकीकरण, कच्चे माल की खरीद, विपणन तथा तकनीकी उन्नयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त करना कठिन होता है।

परंपरागत रूप से लघु उद्यमी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्तिगत बचत, परिवार एवं मित्रों से प्राप्त धन तथा अनौपचारिक ऋणदाताओं से करते रहे हैं। अनौपचारिक स्रोतों की ब्याज दरें अपेक्षाकृत अधिक और शर्तें असमान हो सकती हैं। इसके विपरीत संस्थागत वित्तीय व्यवस्था नियामक ढाँचे, ऋण मूल्यांकन, पुनर्वित्त, क्रेडिट गारंटी और निगरानी जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से अधिक व्यवस्थित वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।

लघु उद्योगों के लिए विशेष विकास बैंक या विकासोन्मुख वित्तीय संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उद्यमियों को ऐसी समग्र सहायता देना है जिससे वे व्यवसाय की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण कर सकें। भारत में औद्योगिक वित्त के विकास के साथ विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/568

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double- Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, July 2026
Impact Factor: 8.2

II. समीक्षा पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं समीक्षात्मक प्रकृति का है। अध्ययन के लिए लघु उद्योग, संस्थागत वित्त, विकास बैंक, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, नीतिगत दस्तावेजों और संस्थागत प्रकाशनों की समीक्षा की गई है। उपलब्ध साहित्य के आधार पर संस्थागत वित्त की भूमिका, वित्तीय साधनों, ऋण वितरण की समस्याओं तथा लघु उद्योगों के विकास के बीच संबंधों का विषयगत विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने के बजाय उपलब्ध साहित्य के आधार पर व्यापक वैचारिक एवं नीतिगत निष्कर्ष विकसित करना है।

लघु उद्योगों में संस्थागत वित्त की आवश्यकता

लघु उद्योगों के लिए वित्त पूंजी निर्माण का प्रमुख साधन है। किसी उद्योग की स्थापना के समय भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के लिए दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर उत्पादन जारी रखने के लिए कच्चे माल, मजदूरी, बिजली, परिवहन, विपणन और अन्य खर्चों हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यक होती है।

लघु उद्यमियों के सामने प्रमुख समस्या यह होती है कि उनकी स्वयं की पूंजी सीमित होती है। अनेक नए उद्यमियों के पास बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक सुरक्षा या पूर्व व्यावसायिक इतिहास भी नहीं होता। संस्थागत वित्तीय संस्थाएँ इस अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उचित ऋण सुविधा उद्यमी को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आधुनिक मशीनरी लगाने, बाजार का विस्तार करने और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने में सहायता करती है।

लघु उद्योगों के विकास बैंक की अवधारणा

लघु उद्योगों के विकास बैंक से आशय ऐसी विशेषीकृत वित्तीय संस्था से है जो लघु एवं संबंधित औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय तथा विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती है। इसका कार्य सामान्य वाणिज्यिक बैंक की तरह केवल जमा स्वीकार करना और ऋण देना नहीं होता, बल्कि इसमें विकासात्मक वित्त की विशेष भूमिका शामिल होती है।

ऐसी संस्था प्रत्यक्ष ऋण देने के साथ-साथ अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध करा सकती है। इसके अतिरिक्त परियोजना मूल्यांकन, उद्यमिता विकास, तकनीकी उन्नयन, वित्तीय परामर्श, बाजार सहायता तथा क्रेडिट गारंटी जैसी सेवाएँ भी प्रदान की जा सकती हैं। इस प्रकार विकास बैंक वित्तीय मध्यस्थ के साथ-साथ औद्योगिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

III. संस्थागत वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत

भारत में लघु उद्योगों को विभिन्न संस्थागत स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। इनमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, विकास वित्तीय संस्थाएँ, सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ तथा विभिन्न सरकारी ऋण एवं क्रेडिट-गारंटी व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

तालिका 1: लघु उद्योगों के संस्थागत वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत

क्रमांक	संस्थागत स्रोत	प्रमुख भूमिका	लघु उद्योगों को लाभ
1	वाणिज्यिक बैंक	ऋण एवं कार्यशील पूंजी	नियमित बैंकिंग एवं ऋण सुविधा
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ग्रामीण उद्यमों को वित्त	ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण पहुँच
3	सहकारी बैंक	स्थानीय स्तर पर वित्त	छोटे उद्यमियों को स्थानीय सहायता
4	विकास वित्तीय संस्थाएँ	दीर्घकालीन एवं विकासात्मक वित्त	विस्तार एवं आधुनिकीकरण
5	पुनर्वित्त संस्थाएँ	अन्य संस्थाओं को वित्तीय समर्थन	ऋण उपलब्धता में वृद्धि
6	सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ	छोटे ऋण	कम पूंजी वाले उद्यमियों को सहायता
7	क्रेडिट गारंटी संस्थाएँ	ऋण जोखिम में कमी	संपार्श्विक की समस्या कम करना
8	सरकारी योजनाएँ	रियायती/लक्षित वित्त	नए उद्यमों एवं कमजोर वर्गों को सहायता

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double- Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, July 2026
Impact Factor: 8.2

विकास बैंक की वित्तीय भूमिका

विकास बैंक लघु उद्योगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण के अंतर्गत मशीनरी ऋण, टर्म लोन, कार्यशील पूंजी तथा विस्तार के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अप्रत्यक्ष वित्त पोषण में वाणिज्यिक या अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराकर अंतिम उद्यमी तक ऋण पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है।

विकास बैंक की एक महत्वपूर्ण भूमिका जोखिम को कम करना भी है। नए और छोटे उद्यमों में ऋण जोखिम अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। इसलिए क्रेडिट गारंटी, परियोजना मूल्यांकन और ऋण निगरानी जैसी व्यवस्थाएँ वित्तीय संस्थाओं को लघु उद्यमों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

पूंजी निर्माण और औद्योगिक विस्तार

संस्थागत वित्त पोषण का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव पूंजी निर्माण पर पड़ता है। पर्याप्त ऋण मिलने पर लघु उद्यम नई मशीनरी, उत्पादन उपकरण और तकनीकी सुविधाओं में निवेश कर सकते हैं। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और लागत में कमी तथा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की संभावना बढ़ती है।

तालिका 2: संस्थागत वित्त के संभावित प्रभाव

क्षेत्र	वित्त पोषण का प्रभाव
पूंजी निर्माण	मशीनरी एवं परिसंपत्तियों में निवेश बढ़ता है
उत्पादन	उत्पादन क्षमता में वृद्धि
रोजगार	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का विस्तार
तकनीक	आधुनिक तकनीक अपनाने की क्षमता
विपणन	नए बाजारों तक पहुँच
प्रतिस्पर्धा	उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार
क्षेत्रीय विकास	ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार
उद्यमिता	नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन

रोजगार सृजन में भूमिका

लघु उद्योग सामान्यतः श्रम-प्रधान गतिविधियों के विकास में सहायक होते हैं। जब संस्थागत वित्त से नई इकाइयों की स्थापना तथा मौजूदा इकाइयों का विस्तार होता है, तो उत्पादन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमों को वित्त उपलब्ध कराने से लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है तथा बड़े शहरों की ओर अनिवार्य प्रवास को कम करने में सहायता मिल सकती है।

तकनीकी आधुनिकीकरण

आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में केवल उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं है। गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता, डिजिटल तकनीक, स्वचालन और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उत्पादन भी आवश्यक है। लघु उद्योगों के पास तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त स्वयं की पूंजी नहीं होती। विकास बैंक एवं अन्य संस्थागत वित्तीय एजेंसियों से प्राप्त दीर्घकालीन वित्त इस समस्या को कम कर सकता है।

तकनीकी उन्नयन के लिए ऋण के साथ तकनीकी सलाह और प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इसलिए आधुनिक विकास बैंक मॉडल में वित्तीय सहायता को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता के साथ जोड़ना अधिक प्रभावी माना जा सकता है।

ग्रामीण औद्योगीकरण में संस्थागत वित्त की भूमिका

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यम कृषि पर निर्भरता को कम करने और गैर-कृषि रोजगार के अवसर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण उद्यमों के लिए वित्तीय संस्थाओं की शाखाएँ, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल आधारित भुगतान तथा स्थानीय वित्तीय मध्यस्थता ऋण तक पहुँच बढ़ा सकती है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double- Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, July 2026
Impact Factor: 8.2

तालिका 3: ग्रामीण लघु उद्योगों में वित्त पोषण की उपयोगिता

आवश्यकता	संस्थागत वित्त की भूमिका
व्यवसाय की स्थापना	प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराना
मशीनरी खरीद	दीर्घकालीन ऋण
कार्यशील पूंजी	दैनिक उत्पादन खर्चों की पूर्ति
कच्चा माल	खरीद हेतु वित्त
विपणन	बाजार विस्तार हेतु वित्त
डिजिटल तकनीक	डिजिटल उपकरणों में निवेश
रोजगार	स्थानीय रोजगार सृजन
व्यवसाय विस्तार	अतिरिक्त क्षमता निर्माण

वित्तीय समावेशन और लघु उद्योग

संस्थागत वित्त पोषण वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण घटक है। जब छोटे उद्यमी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ते हैं, तो उन्हें केवल ऋण ही नहीं बल्कि बचत खाते, डिजिटल भुगतान, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाओं तक भी पहुँच मिल सकती है। इससे उद्यम की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ती है और भविष्य में ऋण प्राप्त करने की क्षमता मजबूत हो सकती है।

डिजिटल वित्तीय सेवाओं ने विशेष रूप से छोटे उद्यमों के लिए लेन-देन को सरल बनाया है। डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन आवेदन और डेटा आधारित क्रेडिट मूल्यांकन भविष्य में छोटे व्यवसायों के ऋण मूल्यांकन को अधिक कुशल बना सकते हैं।

संस्थागत वित्त पोषण की प्रमुख समस्याएँ

लघु उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त की उपयोगिता के बावजूद कई व्यावहारिक समस्याएँ बनी हुई हैं। पहली समस्या ऋण आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया की जटिलता है। छोटे उद्यमियों के पास पर्याप्त वित्तीय दस्तावेज, लेखांकन रिकॉर्ड या व्यावसायिक अनुभव नहीं होने के कारण ऋण प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

दूसरी प्रमुख समस्या संपार्श्विक सुरक्षा की है। नए उद्यमियों के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं होने से वे बैंक की पारंपरिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। तीसरी समस्या वित्तीय साक्षरता की कमी है, जिसके कारण उद्यमी उपलब्ध सरकारी एवं संस्थागत योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते।

तालिका 4: लघु उद्योगों के वित्त पोषण में प्रमुख बाधाएँ

क्रमांक	समस्या	संभावित परिणाम
1	संपार्श्विक की कमी	ऋण आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना
2	जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया	ऋण प्राप्ति में विलंब
3	वित्तीय साक्षरता की कमी	योजनाओं का कम उपयोग
4	ऋण की लागत	लाभप्रदता पर दबाव
5	कमजोर लेखांकन	क्रेडिट मूल्यांकन में कठिनाई
6	बाजार जोखिम	ऋण चुकौती में समस्या
7	बैंक शाखाओं की सीमित पहुँच	ग्रामीण उद्यमों की कठिनाई
8	तकनीकी जानकारी की कमी	आधुनिकीकरण में बाधा

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double- Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, July 2026 Impact Factor: 8.2

संस्थागत वित्त और उद्यमिता विकास

वित्तीय सहायता उद्यमिता विकास का आधार है, लेकिन केवल ऋण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। उद्यमी को व्यवसाय योजना तैयार करने, लागत निर्धारण, बाजार विश्लेषण, डिजिटल मार्केटिंग, लेखांकन और जोखिम प्रबंधन का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए विकास बैंक की भूमिका को वित्तीय सहायता से आगे बढ़ाकर उद्यमिता विकास तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण, मेंटरशिप और परियोजना परामर्श महत्वपूर्ण हैं। इससे ऋण का उत्पादक उपयोग बढ़ सकता है तथा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के जोखिम को भी कम किया जा सकता है।

संस्थागत वित्त की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

1. लघु उद्योगों को अधिक प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न उपाय उपयोगी हो सकते हैं—
2. ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया जाए।
3. संपार्श्विक के स्थान पर व्यवहार्य क्रेडिट-गारंटी व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
4. छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएँ।
5. परियोजना मूल्यांकन और ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब कम किया जाए।
6. महिला एवं प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए लक्षित वित्तीय सहायता विकसित की जाए।
7. क्लस्टर आधारित उद्योगों के लिए सामूहिक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
8. ऋण के साथ तकनीकी, विपणन एवं प्रबंधकीय परामर्श उपलब्ध कराया जाए।
9. डिजिटल लेन-देन और औपचारिक लेखांकन को प्रोत्साहित किया जाए।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं की पहुँच बढ़ाई जाए।
11. ऋण वितरण के साथ ऋण उपयोग एवं व्यवसाय प्रदर्शन की उपयुक्त निगरानी की जाए।

IV. निष्कर्ष

समीक्षित साहित्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लघु उद्योगों के विकास में संस्थागत वित्त पोषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ लघु उद्यमों को पूंजी उपलब्ध कराने के साथ-साथ औद्योगिक विस्तार, तकनीकी आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित कर सकती हैं। संस्थागत वित्त की उपलब्धता छोटे उद्यमियों को अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम करने तथा औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने का अवसर देती है।

हालाँकि, वित्त पोषण की उपलब्धता और उसकी वास्तविक पहुँच के बीच अभी भी अंतर मौजूद है। संपार्श्विक की कमी, दस्तावेजी जटिलता, वित्तीय साक्षरता का अभाव, ऋण स्वीकृति में विलंब तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ लघु उद्यमों की वित्तीय क्षमता को प्रभावित करती हैं। इसलिए भविष्य की संस्थागत वित्त व्यवस्था को केवल ऋण वितरण केंद्रित न होकर ऋण + क्रेडिट गारंटी + तकनीकी सहायता + उद्यमिता प्रशिक्षण + डिजिटल वित्त + बाजार सहायता के समन्वित मॉडल पर आधारित होना चाहिए।

अंततः, लघु उद्योगों के विकास बैंक की प्रभावी स्थापना और संचालन को व्यापक औद्योगिक नीति तथा वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यदि वित्तीय संस्थाएँ छोटे उद्यमियों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप सरल, सुलभ और समयबद्ध वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं, तो लघु उद्योग आर्थिक विकास, रोजगार और स्थानीय उद्यमिता के अधिक मजबूत आधार बन सकते हैं।

संदर्भ

1. बेक, टी., डेमिरगुच-कुंट, ए., और मक्सिमोविक, वी. (2005). विकास में वित्तीय और कानूनी बाधाएं: क्या फर्म का आकार मायने रखता है? द जर्नल ऑफ़ फाइनेंस, 60(1), 137–177.

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double- Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, July 2026
Impact Factor: 8.2

2. बर्गर, ए. एन., और उडेल, जी. एफ. (2006). SME फाइनेंस के लिए एक अधिक पूर्ण वैचारिक ढांचा। जर्नल ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनेंस, 30(11), 2945–2966.
3. बेक, टी., डेमिरगुच-कुंट, ए., और मार्टिनेज पेरिया, एम. एस. (2008). दुनिया भर में SME के लिए बैंक फाइनेंसिंग: कारक, बाधाएं, बिजनेस मॉडल और ऋण देने के तरीके। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्य पत्र, 4785, 1–39.
4. अय्यागरी, एम., डेमिरगुच-कुंट, ए., और मक्सिमोविक, वी. (2011). दुनिया भर में छोटी बनाम नई फर्में: रोजगार, नौकरी सृजन और विकास में योगदान। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्य पत्र, 5631, 1–45.
5. एबोर, जे., और क्वार्टे, पी. (2010). घाना और दक्षिण अफ्रीका में SME विकास के मुद्दे। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 39, 218–228.
6. स्टोरी, डी. जे. (1994). रोजगार सृजन में लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका। स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक्स, 6(4), 253–261.
7. बेक, टी., डेमिरगुच-कुंट, ए., और लेविन, आर. (2005). SME, विकास और गरीबी: विभिन्न देशों के साक्ष्य। जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक ग्रोथ, 10(3), 199–229.
8. डीकिन्स, डी., और हुसैन, जी. (1994). असममित जानकारी के साथ जोखिम का आकलन। इंटरनेशनल स्मॉल बिजनेस जर्नल, 12(4), 55–64.
9. बर्गर, ए. एन., और उडेल, जी. एफ. (1995). छोटी कंपनियों के फाइनेंस में रिलेशनशिप लेंडिंग और क्रेडिट लाइन। द जर्नल ऑफ़ बिज़नेस, 68(3), 351–381.
10. पीटरसन, एम. ए., और राजन, आर. जी. (1994). लेंडिंग रिलेशनशिप के फ़ायदे: छोटे बिज़नेस के डेटा से सबूत। द जर्नल ऑफ़ फाइनेंस, 49(1), 3–37.
11. कोल, आर. ए. (1998). क्रेडिट मिलने में रिलेशनशिप का महत्व। जर्नल ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनेंस, 22(6–8), 959–977.
12. हारहॉफ, डी., स्टाहल, के., और वोयवोडे, एम. (1998). वेस्ट जर्मन कंपनियों का कानूनी रूप, विकास और एग्ज़िट—मैन्युफ़ैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए अनुभवजन्य परिणाम। द जर्नल ऑफ़ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, 46(4), 453–488.
13. कारपेंटर, आर. ई., और पीटरसन, बी. सी. (2002). क्या छोटी कंपनियों का विकास इंटरनल फाइनेंस से सीमित होता है? द रिव्यू ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 84(2), 298–309.
14. हॉल, जी. सी. (2002). बाधाओं को हटाना: फाइनेंस और छोटे बिज़नेस का विकास। जर्नल ऑफ़ स्मॉल बिज़नेस एंड एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट, 9(4), 334–343.
15. फ़ाटोकी, ओ., और स्मिट, ए. वैन डेर (2011). दक्षिण अफ्रीका में नई SMEs के लिए क्रेडिट तक पहुँच में बाधाएँ: सप्लाई-साइड एनालिसिस। अफ्रीकन जर्नल ऑफ़ बिज़नेस मैनेजमेंट, 5(4), 1410–1417.